शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार मीमांसा
मध्यप्रदेश

आईटीआई गोविंदपुरा में प्लेसमेंट ड्राइव 5-6 को

भोपाल। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोविंदपुरा भोपाल में 5 एवं 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक युवा अपने मूल प्रमाण पत्रए बायोडाटा आदि के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, बीई (मैकेनिकल), आईटीआई तथा आयु 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदकों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। बिना मास्क के परिसर पर प्रवेश नहीं मिलेगा।

परीक्षा से जांची शिक्षकों की दक्षता

40 प्रतिशत से कम रिजल्ट वाले हाई स्कूल के शिक्षकों ने दी दक्षता संवर्धन परीक्षा

परीक्षा देते शिक्षक।

अशोकनगर, ब्यूरो।

रविवार को जिला मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दक्षता संवर्धन परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का उद्देश्य उन शिक्षकों की दक्षता जांचना है, जिनके पदस्थापना वाले हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट बीते शिक्षण सत्र में 40 प्रतिशत से कम रहा था। रविवार को इस परीक्षा में कुल 12 शिक्षक उपस्थित हुए, जबकि 14 को नामांकित किया गया था। बताया गया है 14 नामांकित शिक्षकों में से एक की मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक अन्य पर चन्देरी बीआरसी का प्रभार होने के कारण परीक्षा से मुक्त रखा गया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षकों की दक्षता नापने के लिए दक्षता संवर्धन परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्र शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य बीके बमोरिया ने बताया कि सोमवार को मिडिल स्कूल के 106 शिक्षकों की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। रविवार को हुई परीक्षा की निगरानी के लिए प्राचार्य एचएन जाटव को नियुक्त किया गया था।

दक्षता परीक्षा से 7 शिक्षक रहे गैरहाजिर

भास्कर न्यूज़ | सतना

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शून्य से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले हाई स्कूल तथा हायर सेकंड्री स्कूल के शिक्षकों की दक्षता परीक्षा रविवार को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सम्पन्न हुई, जिसमें पंजीबद्ध 43 शिक्षकों में 36 हाजिर हुए, जबकि 7 गैरहाजिर रहे। उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा शिक्षकों को किताब देखकर देनी थी। हाल ही में छात्रों ने भी किताब देखकर ही परीक्षा दी थी। विभाग से जुड़े जानकारों का कहना है कि अगर शिक्षक पठन-पाठन से जुड़ा है तो वह किताब देखकर प्रश्न पत्र हल कर लेगा। बीते वर्ष इसी तरह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 4 शिक्षक फेल हुए थे, जिन्हें विभाग द्वारा बाद में बर्खास्त कर दिया गया था।

माध्यमिक के शिक्षकों का परीक्षण आज

हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी के कैचमेंट एरिया में आने वाली माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों की परीक्षा सोमवार को दोपहर 12 बजे से एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित होगी। इस परीक्षा में 317 शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षकों को निर्धारित समय में उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ-साथ उन्हें अपने साथ फोटोयुक्त आईडी कार्ड-पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।

परीक्षा के दिन ही मूल्यांकन

जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार परीक्षा के उपरांत मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। एक्सीलेंस प्राचार्य इन उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी दिन पूर्ण कराने के बाद अपनी रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय को भेजेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षकों की दक्षता परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र जिला शिक्षा अधिकारी की आईडी में उसी दिन भेजे जाएंगे, जिनका प्रिंट तैयार कर शिक्षकों को वितरित किया जाएगा।

शिक्षकों ने किताब देखकर दी अपनी दक्षता की परीक्षा

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। प्रवेश के हाई व हायर सेकंडरी स्कूल के 1619 शिक्षकों ने रविवार को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित दक्षता मूल्यांकन परीक्षा दी। खास बात यह रही कि सभी उपस्थित शिक्षकों ने किताब देखकर परीक्षा दी। पहले दिन 58 शिक्षक अनुपस्थित भी रहे। अब सोमवार को 6299 शिक्षक परीक्षा देंगे। उधर, बतिया व रीवा सहित कई जिलों में शिक्षकों ने परीक्षा का विरोध किया।

2019-20 में दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम 40 फीसदी से कम आया है। वहां के शिक्षकों का दक्षता मूल्यांकन

- **दक्षता मूल्यांकन परीक्षा शुरू, पहले दिन 58 शिक्षक अनुपस्थित**

रविवार से शुरू हुआ। इस परीक्षा में पहले दिन रविवार को हाई व हायर सेकंडरी स्कूल के 1619 में से 1561 शिक्षक शामिल हुए। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन रविवार को ही किया गया, लेकिन परीक्षा परिणाम गोपनीय रखा। परीक्षा परिणाम मंशानुरूप नहीं आने पर शिक्षकों को दो माह की अवधि दक्षता सुधार के लिए दी जाएगी। जिला स्तर के इन शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी होगा। इसके बाद मार्च के पहले सप्ताह में दोबारा परीक्षा होगी। इसमें भी शिक्षक फेल होते हैं तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।

मिडिल स्कूल के 6299 शिक्षकों की परीक्षा सोमवार को होगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 से 3 बजे तक रहेगा। इसमें सभी विषयों के शिक्षकों की परीक्षा होगी। राजधानी के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा केंद्र रहेगा। विभाग ने दसवीं बोर्ड परीक्षा में 30 फीसद से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा दो बार ली थी। दोबारा फेल होने पर प्रदेश के 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। हालांकि इस बार भी शिक्षक संगठनों ने परीक्षा का विरोध किया।

अनुपस्थित शिक्षकों के जवाब से संतुष्ट होने पर पुनः परीक्षा लेंगे

पहले दिन की परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले 58 शिक्षकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। उपयुक्त कारण होने पर (कोरोना संक्रमण इत्यादि) अनुपस्थित शिक्षकों की पुनः परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए अलग से परीक्षा तिथि की सूचना दी जाएगी।

> प्रदेश के सिर्फ 58 शिक्षक परीक्षा से अनुपस्थित रहे हैं। सभी से उपयुक्त कारण मांगा गया है। परीक्षा का परिणाम गोपनीय रहेगा।
>
> – **जय श्री कियाकत**, आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय

पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर सतना सांसद और विधायक में तकरार

राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल ने एसीएस पंचायत मनोज श्रीवास्तव से की बात, ऑडियो वायरल

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर को लेकर पंचायत राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल और एसीएस मनोज श्रीवास्तव का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। जिसमें मंत्री पटेल पंचायत सचिवों के तबादलों को लेकर श्रीवास्तव से बात कर रहे है। वे कह रहे है कि इनके तबादलों को लेकर सांसद और विधायकों की आपस में तकरार चल रही है। बताया जा रहा है कि ये उनके क्षेत्र का मामला है जिसमें विधायक किसी का तबादला करवाता है तो सांसद निरस्त करवा देता है। ऑडियो में सांसद और विधायक का नाम स्पष्ट नही है किंतु मंत्री के क्षेत्र के ही सांसद-विधायकों की नूराकुश्ती बताई जा रही है। मंत्री ने इस मामले को लेकर मनोज श्रीवास्तव से बात की जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसमें पटेल डाटा एंट्री आपरेटरों के वेतन के मुद्दे की भी बात कर रहे हैं। कह रहे कि वेतन जारी कराईये। जहां जाते है वहां उन्हें घेरा जाता है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन एसीएस गौरी सिंह ने आपरेटरों को बाहर कर दिया था। तब से वे तंगी से गुजर रहे हैं। आप (मनोज श्रीवास्तव) तो उनसे बड़े पावर में है। वेतन दीजिये।

बातचीत का आडियो

रामखेलावन पटेल : डाटा एंट्री आपेरटरों का गौरी सिंह आदेश निरस्त करके गई है ना। आप तो (मनोज श्रीवास्तव) गौरी सिंह से बड़े पावर में है, इनका वेतन दीजिये। कहां जाये बेचार, इनके भी बाल बच्चे पले।

मनोज श्रीवास्तव : अभी आप (राज्यमंत्री)भोपाल में हो की कहां है।

रामखेलावन पटेल : भोपाल में चार-पांच रहेंगे। चार पांच रहोगे न, तो अपन बैठकर डिस्कस कर लेंगे।

रामखेलावन पटेल : कर लीजिये पूरे प्रदेश का मामला है। जहां जाता हूं वहीं घेर लेते हैं और दूसरा हमारा वह इश्यू समाप्त नहीं हुआ। मंत्री जी को बता दीजिये।

मनोज श्रीवास्तव : कौन सा वाला।

रामखेलावन पटेल : वहीं सचिवों वाला

मनोज श्रीवास्तव : अच्छा हां..... बता दूंगा मैं।

रामखेलावन पटेल : वो तो मेरे अधिकार की बात है भाई।

मनोज श्रीवास्तव : अरे वो लेकिन उन्होंने पूछ लिया।

रामखेलावन पटेल : नहीं तो मैं कोई विधायक लिखा तो ट्रांसफर कर दिया और कोई सांसद लिखा तो निरस्त कर दिया और क्या होगा बताइए। ऐसे ट्रांसफर हो जाना, सीएम साहब भी ट्रांसफर नहीं हो जाते।

मनोज श्रीवास्तव : अपन को उसको मैच्योर तरीके से हल करना पड़ेगा। उनके साथ बैठ के।

रामखेलावन पटेल : हां जैसा भी उस दिन बैठे भी थे लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई।

मनोज श्रीवास्तव : नहीं नहीं उनके साथ अलग से बैठेंगे अपन लोग। अपन तीन रहेंगे बस।

इनका कहना है

मनोज श्रीवास्तव और मेरे बीच सामान्य बातचीत हुई है। डाटा एंट्री आपरेटरों के चार-पांच माह से वेतन नहीं मिल रहा है। गौरी सिंह ने आपरेटरों को हटा दिया था। बाद में वे खुद भी बाहर हो गई। सचिवों के तबादले को लेकर प्रदेशभर में ऐसी ही स्थिति है। विधायक कहता है तबादला करो और सांसद लिख देता है तो निरस्त हो जाता है। इसको लेकर केबिनेट मंत्री से बात करेंगे।

रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

कमजोर नतीजे वाले 15 शिक्षकों ने दी परीक्षा

-निज प्रतिनिधि-

गुना। बोर्ड परीक्षा में कमजोर नतीजे देने वाले चुनिंदा 15 शिक्षकों ने रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा दी। परीक्षा की मॉनीटरिंग करने के लिए भोपाल से पर्यवेक्षक भी आए थे। परीक्षा के दौरान बीईओ ने स्कूल के कार्यालय में बैठकर सीसीटीव्ही कैमरे के जरिए परीक्षा की मॉनीटरिंग की। रविवार को हाईस्कूल के 15 शिक्षकों ने अपनी दक्षता साबित करने परीक्षा दी। यह दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चली। कल 4 जनवरी को कैचमेंट की माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक परीक्षा देंगे। उल्लेखनीय है कि यह दक्षता परीक्षा उन शिक्षकों की ली जा रही है जिनका वर्ष 2019-20 में मंडल की कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं परीक्षा में परिणाम 40 प्रतिशत अथवा उससे कम है। इसके अलावा ऐसे हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल जिनका परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत अथवा उससे कम है, के कैचमेंट के माध्यमिक शालाओं के शिक्षक शामिल हैं।

प्रदेशभर में शिक्षकों की दक्षता आंकलन की हुई परीक्षा, कई जिलों में विरोध

भोपाल के एक्सीलेंस में आयोजित परीक्षा के दौरान 15 शिक्षक हुए सम्मिलित

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

पिछले सत्र की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 40 फीसदी से कम रिजल्ट लाने वाले शिक्षकों की विभाग द्वारा रविवार को परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा का शिक्षकों द्वारा कई जिलों में विरोध किया गया।

इस परीक्षा का कई जिलों में विरोध देखने को सामने आया। राजगढ़ और आगर मालवा में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया कि जिन शिक्षकों ने अपने विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 40 फीसदी से ऊपर दिया है। उनकी भी विभाग ने परीक्षा आयोजित करवाई है। आरोप लगाया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारियों ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अपनी दुश्मनी भुनाने के लिए यह नाम परीक्षा के लिए सूची में जोड़कर विभाग के संज्ञान में दिए हैं। शिक्षकों का कहना था कि यह परीक्षा पूरी तरह से विसंगति पूर्ण है। भोपाल में जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि यहां एक्सीलेंस स्कूल में शिक्षकों की परीक्षा करवाई गई। जिसमें 15 शिक्षक उपस्थित हुए। नितिन सक्सेना ने बताया कि परीक्षा पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपादित हुई है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की परीक्षा का परिणाम विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

इधर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौर ने विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी से फिर मांग की है कि उन शिक्षकों के साथ न्याय किया जाए जिनके विद्यालयों का रिजल्ट 40 प्रतिशत से ऊपर रहा है। शासकीय अध्यापक संघ के संयोजक उपेंद्र कौशल ने सरकार से मांग उठाई है कि दक्षता आंकलन परीक्षा में जो शिक्षक अगर अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति ना देते हुए वेतन वृद्धि रोकने सहित कोई अन्य दोष निर्धारित किया जाए।

कॉलेजों में छठवें चरण की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पांच तक

भोपाल। स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों में छठवें चरण की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक चालू है। आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी सरकारी कॉलेज के हेल्प सेंटर से शनिवार तक कराया जा सकेगा। कॉलेज, पाठ्यक्रम एवं विषय समूह को तय करने के लिए 4 जनवरी तक का समय दिया गया है। सीएलसी चरण की मेरिट सूची 4 जनवरी को दोपहर 3 बजे जारी होगी। आवंटित कॉलेजों में पोर्टल के माध्यम से डिजिटल ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 4 एवं 5 जनवरी को किया जा सकेगा।

एडमिशन

दक्षता आकलन परीक्षा में 4 शिक्षक रहे अनुपस्थित

उच्चतर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 172 शिक्षकों ने दी परीक्षा

जागरण, रीवा। 40 फीसदी से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले उच्चतर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दक्षता परीक्षा रविवार को हुई। परीक्षा में शिक्षकों को किताब लेकर बैठने की अनुमति रही। इस परीक्षा में 176 शिक्षकों को शामिल होना था, जिसमें से 4 शिक्षक अनुपस्थित रहे। जबकि 172 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए। अब अनुपस्थित शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शोकॉज नोटिस दिया जायेगा। जबाबी कार्यवाही होने के बाद इन शिक्षकों की दोबारा परीक्षा भी कराई जा सकती है। बहरहाल, अब सोमवार को भी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दक्षता परीक्षा होनी है। इस परीक्षा की तैयारी में जिला शिक्षा अधिकारी का अमला देर शाम तक व्यस्त रहा।

गौरतलब है कि शिक्षकों की दक्षता का आंकलन करने लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश पर यह परीक्षा हो रही है। परीक्षा के लिए जिले में तीन केंद्र बनाए गए हैं। जुलाई 2020 में माशिमं द्वारा जारी परिणाम में 40 प्रतिशत से कम जिन विद्यालयों के छात्र उत्तीर्ण हुए, उन विद्यालयों के शिक्षकों का परीक्षण इस परीक्षा के जरिये किया जाना है। इसके अलावा बीते सत्र की अन्य परीक्षाओं में 40 प्रतिशत से कम रिजल्ट देने वाले विद्यालय के शिक्षक भी इसमें बैठेंगे। इस परीक्षा जिले के 856 शिक्षकों को शामिल होना रहा। इन शिक्षकों की दक्षता परीक्षा के लिए मार्तण्ड स्कूल क्रमांक एक, मार्तण्ड स्कूल क्रमांक दो और मॉडल स्कूल को केंद्र बनाया गया है।

सोमवार को माध्यमिक की परीक्षा

सोमवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें कैचमेंट की माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। तीन परीक्षा केन्द्रों में अंग्रेजी के 13, हिंदी के 54, गणित के 120, उर्दू के 2, संस्कृत के 39, विज्ञान के 166, समाजिक विज्ञान के 276 शिक्षक शामिल होंगे। इसी तरह मार्तण्ड क्रमांक एक में 189, मार्तण्ड 2 में 205 और मॉडल स्कूल में 276 शिक्षक परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए समय दोपहर 12 से 3 बजे तक का निर्धारित किया गया है।

कमिश्नर के आदेश को रद्दी की टोकरी में डाला

सिरमौर बीआरसीसी सुधीर साकेत के खिलाफ जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं

जागरण, रीवा। सिरमौर जनपद शिक्षा केंद्र में पदस्थ बीआरसीसी सुधीर साकेत को हटाने की सिफारिश जेडी लोक शिक्षण रीवा सम्भाग ने की थी। इस पर कमिश्नर ने गत सितम्बर माह में आदेश भी जारी किए। इसके बावजूद डीपीसी द्वारा उक्त आदेश पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता सिद्धनाथ पांडे की शिकायत पर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग से जांच कराई गई थी। जांच दल ने अपना निष्कर्ष देते हुए गत 17 सितम्बर को रिपोर्ट कमिश्नर को दी। इस रिपोर्ट में सुधीर साकेत को वित्तीय अनियमितताओं का दोषी मानते हुए वित्तीय नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए स्पष्ट रूप से लिखा गया।

24 सितम्बर को कमिश्नर ने लिखा था पत्र : मामले में बताते चलें कि जेडी रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन पर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 3473 में 24 सितंबर 2020 को कलेक्टर रीवा को पत्र लिखकर प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश दिया था। कलेक्टर रीवा ने उक्त पत्र को डीपीसी को मार्क करते हुए अभिमत सहित प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिस पर पिछले 3 महीने में डीपीसी द्वारा लगभग कोई कार्यवाही नहीं की गई।

शाखाओं में घुमाते रहे फाइल

बताते हैं कि डीपीसी द्वारा कमिश्नर, कलेक्टर के आदेश के बावजूद बीआरसीसी पर कार्यवाही नहीं की गई। उलटे कार्यालय की अलग-अलग शाखाओं में फाइल को घुमाते रहे और आरोपी बीआरसीसी से असंबद्ध दस्तावेज प्राप्त कर गलत तरीके से प्रकरण में लिखा पढ़ी की गई है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने डीपीसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह अत्यंत खेद का विषय है कि प्रथम दृष्टया तो जांच होने में 10 महीने लगभग का समय लग गया और जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कमिश्नर द्वारा आदेश करने के बावजूद डीपीसी रीवा द्वारा अपने कार्यालय में फाइल को सुनवाई एवं साक्ष्यों के नाम पर रखने का काम किया और कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया।

न्यायालय में लगाई गई याचिका भी हो चुकी है समाप्त

जानकारी के अनुसार बीआरसीसी श्री साकेत को तत्कालीन कलेक्टर द्वारा दिसंबर 2019 में 3 साल से ज्यादा की अवधि पूर्ण होने पर वापस कर दिया गया था। इसके उपरांत बीआरसीसी द्वारा कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। श्री पांडे ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा श्री साकेत की याचिका निरस्त कर दिया गया तथा उनके सारे लाभ समाप्त कर दिए गए हैं। इस बाबत आदेश गत 10 दिसंबर 2020 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है।

बिना बिल के भुगतान की शिकायत

शिकायत में बीआरसीसी साकेत पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यालय से कुछ ऐसे भुगतान किए हैं, जिनके बिल ही कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए। इसके अलावा सिरमौर में कुछ फर्जी फर्मों के नाम पर बिल को कम्प्यूटर से टाइप कर फर्जी भुगतान किए गए एवं उनका आहरण अपने पक्ष में कर लिया गया।

रिजल्ट में गड़बड़ी का ठीकरा छात्रों पर ही फोड़ने की तैयारी

एडी द्वारा गठित समिति की जांच अब तक नहीं हुई पूरी

जागरण, रीवा

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के त्रुटिपूर्ण रिजल्ट मामले में अब तक जांच पूरी नहीं हुई है। एडी रीवा द्वारा गठित समिति भी जांच को लेकर अब टालमटोल कर रही है। अब तक की जांच में समिति ने रिजल्ट में गड़बड़ी का ठीकरा भी छात्रों पर फोड़ने की तैयारी कर रखी है। इस लिहाज से समिति के जरिये पीड़ित छात्रों को न्याय मिल पाना मुश्किल लग रहा है। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातक द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने के निर्देश दिए थे। यह जनरल प्रमोशन पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंक व सेशनल के अंकों के आधार पर देना था। इसके उलट गत माह महाविद्यालय ने जो जनरल प्रमोशन के रिजल्ट जारी किए, उसमें अधिकांश छात्र फेल हो गए। छात्रों का आरोप है कि पिछली कक्षाओं में जिन छात्रों को अच्छे अंक मिले थे, उन्हें भी महाविद्यालय ने फेल कर दिया। जबकि मप्र शासन ने पिछली कक्षाओं में जो अंक मिले थे, उसके समतुल्य ही अंक देने के लिए कहा था परंतु कई छात्रों को पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंकों की तुलना में 200-200 कम अंक दिए गए। महाविद्यालय प्रबंधन की इस गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने हफ्तेभर हंगामा किया। इस पर एडी रीवा डॉ पंकज श्रीवास्तव ने मामले की जांच कराने का आश्वासन छात्रों को दिया। इसके उपरांत उन्होंने तीन सदस्यीय समिति गठित की। इस समिति ने एडी रीवा ने मामले की जांच के लिए कहा था, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

रिजल्ट सुधार कर संतुलन की कवायद

समिति का संयोजक एडी रीवा ने जीडीसी प्राचार्य डॉ नीता सिंह को बनाया गया। समिति में बतौर सदस्य डॉ विभा श्रीवास्तव व मॉडल साइंस के प्राध्यापक डॉ एसएन शुक्ला को भी शामिल किया गया। बताते हैं कि इस समिति की जांच धीमी गति से चल रही है। इधर, इसका फायदा उठाते हुए महाविद्यालय द्वारा सभी रिजल्ट को सुधारने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ताकि समिति की रिपोर्ट और गड़बड़ी को छुपाने में संतुलन बैठाया जा सके।

इन कक्षाओं के रिजल्ट में थी शिकायत

बता दें कि सर्वाधिक छात्र बीएससी बॉटनी और बायोटेक्नालॉजी में फेल हुए हैं। इसके अलावा बीए, बीएससी ऑनर्स द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर में भी कई छात्र अनुत्तीर्ण हुए। एमएससी द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप छात्रों ने लगाये हैं। इन त्रुटिपूर्ण परिणामों की ऑनलाइन अंकसूची महाविद्यालय ने जारी कर दी थी, जिसके बाद अब सुधार की कार्यवाही चल रही है। इस पर भी महाविद्यालय ने मामले में किसी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना अब तक उचित नहीं समझा।

एमए, एमएससी के रिजल्ट अभी रुके

वहीं, महाविद्यालय ने एमए, एमएससी, एमकॉम समेत कुछ अन्य स्नातकोत्तर कक्षाओं के परिणाम अभी जारी नहीं किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार इन कक्षाओं की परीक्षा विगत सितम्बर माह में हो चुकी है। ओपेन बुक परीक्षा प्रणाली के तहत हुई इन परीक्षाओं के परिणाम जारी करने में महाविद्यालय अब देरी कर रहा है। हालांकि स्नातक अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर के परिणाम तो जैसे-तैसे महाविद्यालय ने हाल ही में जारी कर दिए हैं।

भाषाएं सीखने का अवसर

एक वर्षीय अरबी, फारसी और उर्दू कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति परिषद की निगरानी में चल रहे कौमी कौंसिल बराए फरोगे उर्दू जबान, भारत सरकार के एक वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अरबी भाषा, एक वर्षीय प्रमाण.पत्र फारसी (परशियन) कोर्स और एक वर्षीय उर्दू डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्रारंभ हो गये हैं। अरबी, फारसी और उर्दू भाषा सीखने के इच्छुक इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, नियत की गई है। अरबी कोर्स में प्रवेश के लिए उर्दू की प्रारंभिक शिक्षा के अतिरिक्त उर्दू लिखने और समझने का ज्ञान भी आवश्यक है। फारसी कोर्स में प्रवेश के लिए उर्दू एवं अंग्रेजी लिखने और पढ़ने का ज्ञान आवश्यक है। उर्दू डिप्लोमा कोर्स में शैक्षणिक योग्यता की कोई शर्त नहीं है।

आयु सीमा की बाध्यता नहीं है

तीनों पाठ्यक्रमों में आयु सीमा की बाध्यता नहीं है। प्रति कोर्स 200 रुपये पंजीयन शुल्क प्रवेश के समय जमा होंगे। इसके अलावा अन्य कोई फीस नहीं ली जाएगी। कोर्स की किताबें नि:शुल्क मिलेंगी। प्रवेश पत्र सीमित हैं। प्रवेश पत्र की छाया प्रति स्वीकार नहीं की जायेगी। फार्म मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी के कार्यालय, मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल में कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए अकादमी के दूरभाष क्रमांक 0755-2551691 पर कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

दक्षता आंकलन परीक्षा

सात ने छोड़ा एग्जाम जल्द होगी कार्रवाई

स्टार समाचार | सतना

हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के कम आए परीक्षा परिणाम को लेकर शासकीय टीचरों की दक्षता आंकलन परीक्षा रविवार को आयोजित की गई जिसमें हाईस्कूल के 7 शिक्षकों ने परीक्षा छोड़ी है और वो अनुपस्थित रहे। बताया गया कि शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यकंट क्र. 1 के शिक्षण सत्र 2019-20 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शून्य से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले एवं हाईस्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल के केचमेंट की हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के शिक्षकों की दक्षता आंकलन के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें 50 शिक्षकों को शामिल होना था लेकिन इसमें 43 शिक्षक ही शामिल हुए जिसमे हाईस्कूल के 40 एवं हायर सेकेंडरी के 3 शिक्षक शामिल थे। जिला शिक्षा अधिकारी कमल

सिंह कुशवाह ने बताया कि अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्यवाई की जाएगी। बताया गया कि परीक्षा में आब्जर्वर केपी तिवारी सहायक संचालक जेडी आफिस रीवा थे।

परीक्षा आज

बताया गया कि सोमवार को आज फिर शिक्षण सत्र 2019-20 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शून्य से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले एवं हाईस्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल के केचमेंट की माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों को सूचित किया गया है कि संचालनालय द्वारा जारी नवीन तिथि अनुसार परीक्षा केन्द्र शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यकंट क्र.1 में निर्धारित समय में उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हों तथा अपने साथ फोटोयुक्त आईडी कार्ड/पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

बीयू: पत्राचार स्नातक कोर्स में नहीं हो सकेंगे प्रवेश

बीयू : नैक रेंकिंग के अभाव में यूजीसी ने लगाया प्रतिबंध

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पत्राचार विभाग में स्नातक कोर्स में इस सत्र में प्रवेश नहीं हो सकेंगे। ऐसा यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा लबाए गए प्रतिबंध के कारण हो रहा है। बीयू को नैक का ए-प्लस एग्रेडेशन नहीं मिल सका है, इसलिए यूजीसी ने बीयू के पत्राचार विभाग के सत्र 2020-21 में स्नातक के कोर्स बीए और बीकॉम में नये प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन वर्तमान में द्वितीय और तीसरे वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षाएं अगले माह में होंगी।

बीयू को नैक से प्राप्त करना होगा ए-प्लस एग्रेडेशन

दरअसल, प्रवेश की पात्रता के अनुसार देशभर के सभी विश्वविद्यालयों को नैक में 3.26 अंक हासिल करना जरूरी है। नैक से 3. 26 हासिल नहीं करने की स्थिती में विवि डिग्री में प्रवेश नहीं दे पाएंगे, लेकिन वह डिप्लोमा कोर्स संचालित जरूर कर सकेंगे। बीयू को भी नैक का ए-प्लस ग्रेड प्राप्त करने के लिए 3.26 अंक हासिल करना अनिवार्य है। जबकि बीयू को नैक में 2.5 अंक से बी एग्रेडेशन प्राप्त है। बीयू को पत्राचार प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने नैक में 3.26 अंक हासिल करने होंगे, जिसके लिए एप्लीकेशन किए जा रहे हैं। बीयू ए-एग्रेडेशन हासिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए बीयू कों प्रोफेसरों की कमी के साथ ही अन्य संसाधानों को जुटाना होगा, जिनके अभाव में नैक की ए ग्रेडिंग प्राप्त नहीं कर सका है।

पूर्व प्रवेशित विद्यार्थियों की डिग्री हो सकेगी पूरी

पत्राचार विभाग के वर्तमान में द्वितीय और तृतीय वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे। बीयू के बीए और बीकाम की परीक्षाएं अगले माह में लेगा। क्योंकि अभी पूरक परीक्षाओं के रिजल्ट आना शेष है। जैसे ही उनके रिजल्ट जारी हो जाते हैं। बीयू ओपन बुक से द्वितीय और तीसरे वर्ष की परीक्षाएं कराएगा। इसका टाइम टेबिल बीयू आईओडी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

आयुष कॉलेजों में 4 जनवरी से शुरू होंगी नियमित कक्षाएं

भोपाल। कोरोना संकट के कारण बीते नौ महीनों से बंद चल रहे आयुष महाविद्यालयों होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक और सिद्धा कॉलेज में अब नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। केन्द्रीय आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने सभी राज्यों को आदेश जारी करते हुए 4 जनवरी के पहले नियमित कक्षाएं शुरू करने का निर्णय करने के लिए कहा, बीते मार्च महीने से कोरोना के कारण आयुष कॉलेजों की भी कक्षाएं बंद कर दीं गईं थी। मप्र के आयुष विभाग के उपसंचालक डॉ सुशील तिवारी ने बताया कि केन्द्रीय आयुष मंत्रालय के आदेश के बाद विभाग ने मप्र के आयुष कॉलेजों को भी आज से नियमित शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

आरजीपीवी: प्रैक्टिकल एग्जाम आज से, 20 से होंगे थ्यौरी पेपर

भोपाल। आरजीपीवी प्रथम सेमेस्टर के पूर्व व द्वितीय से आठवें सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम से कराने जा रहा है। इस परीक्षा में यूजी-पीजी के प्रथम सेमेस्टर और लेटरेल एंट्री से तीसरे सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे। बीई, बीफार्मा, एमसीए सहित सभी कोर्स के सातवें और अंतिम सेमेस्टर की थ्यौरी और प्रायोगिक परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। चार जनवरी यानि सोमवार से सभी विद्यार्थियों के ऑनलाइन प्रैक्टिकल होंगे। जबकि थ्यौरी एग्जाम 20 जनवरी से शुरू होंगे। सातवें और आठवें सेमेस्टर के एग्जाम ऑनलाइन और शेष विद्यार्थियों की परीक्षा ओपन बुक सिस्टम से होगी।

ऑफलाइन एग्जाम की कॉपी स्कैन कर भेजना होगी

आरजीपीवी 4 से 18 जनवरी तक बीई बीफार्मा, एमसीए सहित अन्य कोर्स के द्वितीय सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल एग्जाम कराएगा। जिसमें डेढ लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। 20 जनवरी से उनके थ्यौरी एग्जाम शुरू होंगे। ऑनलाइन परीक्षा दो और ऑफलाइन एग्जाम तीन घंटे की होगी। इसमें ऑफलाइन एग्जाम में विद्यार्थी को अपनी कॉपी स्कैन कर तत्काल भेजना होगी। इसके बाद ई-मेल और डाक से भेजी गई कॉपियों को आरजीपीवी स्वीकृत नहीं करेगा, इससे वे फेल हो जाएंगे।

15 मिनट पहले अपलोड होगा पेपर

प्रथम सेमेस्टर के पूर्व व दूसरे से छठवें सेमेस्टर के एग्जाम ऑफलाइन ओपन बुक सिस्टम से होंगे। आरजीपीवी विद्यार्थी के एकाउंट में परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पेपर अपलोड करेगा। उनके आंसर विद्यार्थियों को तीन घंटे में लिखकर उत्तरपुस्तिका को अपने नजदीक के परीक्षा केंद्र और पोर्टल एकाउंट में स्कैन कर तत्काल जमा करना होगी। इसके बाद ई-मेल और डाक से भेजी गई कॉपियों को आरजीपीवी स्वीकृत नहीं करेगा। उन्हें गैरहाजिर मानकर फेल कर दिया जाएगा। आरजीपीवी कॉपी जमा करने के लिए जल्द ही केंद्रों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करेगा। आरजीपीवी सभी कोर्स में प्रवेश लेने वाले सभी प्रथम और तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं फरवरी व मार्च में लेगा। ये परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन होने पर निर्णय होना शेष है।

बीयू: पत्राचार से बीए और बीकॉम में नहीं होंगे एडमिशन

ए प्लस एक्रिडेशन नहीं होने से यूजीसी ने लगाई रोक

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

मो.नं. 9893231237

बरकतउल्ला विवि (बीयू) के पत्राचार विभाग में अब बीए और बीकॉम में यूजी में एडमिशन नहीं होंगे। यूजीसी ने नैक का ए-प्लस एक्रिडेशन नहीं होने से इस पर रोक लगा दी है। पहले से प्रवेशित सेकंड और थर्ड ईयर के एग्जाम फरवरी में होंगे।

बीयू के पास वर्तमान में नैक का बी एक्रिडेशन मिला हुआ है, लेकिन इस समय विवि में न तो नियमित फैकल्टी है और न स्टूडेंट्स के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। सूत्र बताते हैं कि नैक के लिए मापदंड पूरे नहीं करने के कारण बीयू आवेदन भी नहीं कर पा रहा है। इसी का परिणाम है कि यूजीसी ने पत्राचार विभाग के सत्र 2020-21 में यूजी के कोर्स बीए और बीकॉम में नए प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है।

डिप्लोमा कोर्स संचालित कर सकेगा: बीयू में नैक ए प्लस नहीं होने के कारण वह डिग्री में प्रवेश नहीं दे सकता, लेकिन डिप्लोमा कोर्स संचालित होंगे। वर्तमान में द्वितीय और तृतीय वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी डिग्री पूरी कर पाएंगे। बीयू बीए और बीकॉम की परीक्षाएं अगले माह में लेगा।

यूजीसी ने मापदंड तय किए हैं

पत्राचार में डिग्री कोर्स चलाने के लिए यूजीसी ने सभी विवि के लिए मापदंड तय किए हैं। उसी के अनुसार यूजीसी ने बीयू के पत्राचार विभाग में बीए व बीकॉम के यूजी कोर्स में प्रतिबंध लगाया है।

प्रो. आरजे राव, कुलपति, बीयू

पीपुल्स समाचार

चिनार पार्क में मप्र पालक महासंघ की बैठक, लगाए मांगों संबंधी पोस्टर

भोपाल। मप्र पालक महासंघ की बैठक रविवार को चिनार पार्क में हुई। बैठक स्थल पर विभिन्न मांगों की तख्तियां लगाई गई थीं। इस दौरान कहा गया कि फीस रेगुलेशन एक्ट में बहुत विसंगतियां हैं। सरकार ने बिना आय-व्यय का ब्यौरा देखे निजी स्कूलों को 10 प्रतिशत फीस प्रतिवर्ष बढ़ाने का अधिकार दे दिया है, जबकि तीन साल का ऑडिट कराकर 3 से 5 प्रतिशत फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाए। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने कहा कि प्राइवेट स्कूल, हाईकोर्ट और राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। इनकी मान्यता निरस्त की जाए। सभी क्लासेस में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य की जाएं। बैठक में सर्व सहमति से कमल विश्वकर्मा को संगठन का तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया। भोपाल जिला अध्यक्ष के रूप में मुकेश गुप्ता को चुना गया। प्रदेश सलाहकार नरेंद्र भार्गव एवं आरएस यदुवंशी बनाए गए।

चालीस से कम स्टूडेंट वाले एक लाख स्कूल किए जाएंगे मर्ज

सीएम राइज योजना के तहत किए जाएंगे अपग्रेड

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

मो.नं. 9893231237

सीएम राइज योजना के तहत प्रदेश के 9200 स्कूलों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 40 से कम बच्चों वाले स्कूलों को बंद कर एक शाला एक परिसर के तहत मर्ज किया जाएगा। संकुल प्राचार्यों से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है।

इसी योजना के तहत दो साल पहले 45,384 स्कूलों को 20,656 परिसर में मर्ज किया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा एक शाला, एक परिसर के तहत 40 से कम नामांकन वाली 40102 प्राथमिक शाला और 6221 मिडिल स्कूलों को मर्ज किया गया। तब अकेले भोपाल में 413 स्कूल मर्ज किए गए थे। अब एक लाख वह स्कूल चिह्नित किए गए हैं, जिनमें 40 से कम एडमिशन हुए हैं। संकुल केन्द्रों से इनकी जानकारी मांगी गई है। ज्ञात हो, शिक्षकों के ट्रांसफर होने के बाद पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, इस कारण यह पता नहीं चल रहा है कि किस स्कूल में बच्चों के हिसाब से कितने शिक्षक हैं। स्कूल बंद कर मर्ज किए जाएंगे, तो स्टाफ भी मर्ज होगा।

पांच किमी दूरी पर स्कूल की योजना ठंडे बस्ते में: प्रदेश सरकार की योजना थी कि हर पांच किमी में एक स्कूल होगा। अब स्कूलों को मर्ज कर 10 से 20 किमी दूरी बढ़ा दी गई है। पैरेंट्स की मानें तो कई स्कूल अब बहुत अधिक दूरी पर हैं।

मजदूर के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा

लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट गए थे। अब फिर से सब कुछ सामान्य होने के बाद प्रवासी मजदूर वापस अपने काम पर मध्यप्रदेश में लौट आए हैं। इसमें मजदूरों के 5 से 14 वर्ष के करीब सवा लाख बच्चे भी शामिल हैं और स्कूलों में प्रवेश से वंचित हैं। अब शासन की बड़ी चिंता इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का है। इसी के तहत मप्र स्कूल शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है। विभाग का मानना है कि करीब सवा लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। इस संबंध में

राज्य शिक्षा केंद्र ने आंकड़े जारी किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा छतरपुर जिले में बच्चों की संख्या 12,822 हैं। इसके बाद टीकमगढ़ जिले में 9379 बच्चे हैं। विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी कर कहा है कि प्रवासी मजदूरों के साथ वापस आए बच्चों का सत्यापन कर उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए। ऐसे बच्चे जो 5 से 14 साल के हैं और शिक्षा से वंचित है उन बच्चों को कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल, बालिका छात्रावास, बालक छात्रावास, आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र व ब्रिज कोर्स के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए महिला व बाल विकास विभाग व अन्य सामाजिक संस्थाएं मदद करेंगी।

83,890 प्राथमिक स्कूल | **30,341** माध्यमिक स्कूल

71,86,000 बच्चों की संख्या

4,740 हाईस्कूल | **3,815** हायर सेकंडरी

38,99,000 बच्चों की संख्या

स्कूलों में हुए दाखिले

1,25,08,648 2020 में कुल एडमिशन

81,32,800 सरकारी स्कूलों में दाखिले

43,75,848 निजी स्कूलों में दाखिले

> प्रवासी मजदूरों के करीब सवा लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। उन्हें स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रेरित किया जाएगा।
>
> – **लोकेश कुमार जाटव**, आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र

(इनपुट : अंजली राय)

प्रवासी मजदूरों के बच्चे जो शिक्षा से वंचित है

9वीं से पीएचडी तक के संस्कृत छात्रों को 25 हजार तक छात्रवृत्ति

केंद्रीय संस्कृत विवि ने 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे

भास्कर न्यूज | रांची

दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा और देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा के विकास और संवर्द्धन के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने इसे बढ़ावा देने के लिए संस्कृत पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को सालाना छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है।

9वीं से पीएचडी तक के संस्कृत छात्रों को प्रति वर्ष 5 हजार से 25 हजार रुपए तक छात्रवृत्ति मिलेगी। 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। पूरी राशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में जाएगी। संस्कृत भाषा विकास योजना के अंतर्गत यह छात्रवृत्ति वैसे छात्रों को देनी है, जो संस्कृत पाठशालाओं, संस्कृत महाविद्यालयों, संस्कृत विश्वविद्यालयों, माध्यमिक, उच्च-माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। यह छात्रवृत्ति वर्ष 2020-2021 के लिए होगी, जो पिछली कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी। छात्रवृत्ति का भुगतान जुलाई में होगा। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे। इंटर तक के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए केवल संस्कृत विषय के अंकों के आधार पर वरीयता क्रम तैयार किए जाएंगे, परंतु संस्कृत ऑनर्स के लिए पूर्व के सभी विषयों के पूर्णांक पर वरीयता क्रम निर्धारित होंगे।

10-12वीं में 40 प्रतिशत से कम रिजल्ट वाले स्कूलों के शिक्षकों की दक्षता जांचने हुई परीक्षा

ओपन बुक एग्जाम: 100 में 50 अंक भी नहीं ला सके 6 शिक्षक

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9893231237

बीते साल बोर्ड परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम रिजल्ट वाले स्कूलों के शिक्षकों की दक्षता जांचने के लिए रविवार को भोपाल सहित सभी जिलों में परीक्षा हुई। राजधानी में सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में दक्षता परीक्षा में 15 शिक्षक शामिल हुए। ओपन बुक एग्जाम के बाद मूल्यांकन किया गया।

बताया जाता है कि भोपाल में परीक्षा में शामिल 15 में से छह शिक्षक 100 में से 50 नंबर भी नहीं ला पाए। प्रदेशभर में 1545 शिक्षकों ने परीक्षा दी, जबकि 90 शिक्षक अनुपस्थित रहे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दक्षता परीक्षा रविवार और सोमवार को दो दिन आयोजित की गई है। रविवार को सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में

भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में रविवार को परीक्षा देने जाते शिक्षक-शिक्षिकाएं।

दोपहर 12 से 3 बजे तक हुई परीक्षा में हाईस्कूल व हायर सेकंडरी के 15 शिक्षक शामिल हुए। इनमें गणित के 10, विज्ञान के 2, इतिहास का एक और दो अन्य विषयों के शिक्षक थे। अधिकतर शिक्षक लगभग एक घंटा पहले ही एक्सीलेंस स्कूल पहुंच गए थे। सभी अपने साथ किताब लेकर आए थे। बताया जाता है कि तत्काल मूल्यांकन में 6 शिक्षक ऐसे हैं, जिन्हें 50 से कम अंक मिले हैं, जबकि बाकी को 65 व 70 अंक मिले हैं।

90 शिक्षकों को नोटिस जारी

प्रदेशभर में पहले दिन की परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले 90 शिक्षकों को विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन शिक्षकों की पुनः परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए अलग से परीक्षा तिथि की सूचना दी जाएगी। नोटिस का जबाव तीन दिन में मांगा गया है। उपयुक्त जबाव नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आज मिडिल स्कूल के शिक्षकों की होगी परीक्षा

सोमवार को मिडिल स्कूलों के शिक्षकों की दक्षता जांची जाएगी। प्रदेशभर में इस परीक्षा में 6 हजार 299 शिक्षक शामिल होंगे। इनमें राजधानी के 52 शिक्षक शामिल हैं। इनकी परीक्षा भी सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में दोपहर 12 से 3 बजे तक ओपन बुक से होगी।

गृहमंत्री के समक्ष जताया विरोध

इधर, दक्षता परीक्षा के विरोध में दतिया में शिक्षकों ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का घेराव किया। गृहमंत्री ने शिक्षकों को सेवा से बाहर नहीं करने का आश्वासन दिया। वहीं रीवा में भी शिक्षकों ने परीक्षा का विरोध किया। शिक्षकों का कहना है कि अधिकारियों की दक्षता क्यों नहीं परखी जाती है।

आज अधिकारी तो कल मंत्रियों की होगी क्लास

विकास का रोडमैप बनाने की तैयारी : मंत्रियों से वन-टू-वन बात करेंगे मुख्यमंत्री, स्थान अभी तय नहीं

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण से उबर रहे मध्य प्रदेश में विकास का नया दौर शुरू करने और सुशासन को लेकर राज्य सरकार सख्त है। शनिवार को धार्मिक यात्रा से लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के आला अधिकारियों के सामने रोडमैप रख दिया। उन्हें सरकार की प्राथमिकताएं बता दीं। अब मैदानी अधिकारियों और मंत्रियों से बात होगी। मुख्यमंत्री सोमवार को कलेक्टर-कमिश्नर, डीआइजी और आइजी से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बात करेंगे। वहीं मंगलवार को मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा होगी। अभी मंत्रियों को राजधानी के नजदीक स्थित कोलार गेस्ट हाउस पहुंचने को कहा गया है। हालांकि ऐनवक्त पर स्थान में बदलाव होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री चौहान ने नए साल में अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तीकरण, माफिया के खिलाफ अभियान, स्वास्थ्य-शिक्षा सहित 12 सूत्र तय किए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इन पर सभी को मिलकर काम करना है। रविवार को मंत्रिमंडल में दो और मंत्री (तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत) के शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से बात करने की इच्छा जताई है। वे नए साल में पहली बार मंत्रियों से रूबरू होंगे। इसके लिए पांच जनवरी को मंत्रियों की वन-टू-वन बैठक बुलाई है।

सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में मुख्यमंत्री सरकार की प्राथमिकताएं बताएंगे और मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपेंगे। मुख्यमंत्री यह पहले ही कह चुके हैं कि सरकार जनता के लिए है और सुशासन सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने अधिकारियों से जनता के काम बिना परेशानी के निश्चित सीमा में लिए-दिए बगैर करने को कहा है और जनता के बीच जाकर फीडबैक लेने की जिम्मेदारी अधिकारियों के साथ मंत्रियों को भी दी है।

माफिया के खिलाफ सख्ती पर होगी बात

मुख्यमंत्री साल की पहली कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस सोमवार को कर रहे हैं। इसमें कलेक्टर-कमिश्नर, आइजी, डीआइजी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। बैठक में मिलावटखोर, भू-माफिया, अवैध उत्खनन, शिटफंड कंपनियों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के अलावा कानून व्यवस्था, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा होगी। अधिकारियों से पूछा जाएगा कि उनके क्षेत्र में मिलावटखोर और भू-माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की क्या स्थिति है। इसके अलावा सरकार नए साल में रोजगार सृजन और पर्यटन में वृद्धि पर काम कर रही है।

मुख्य सचिव नहीं, इसलिए कैबिनेट नहीं

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस मंगलवार को भोपाल में नहीं हैं इसलिए हर मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। मुख्य सचिव बैंस और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा दिल्ली में रहेंगे। चुनाव में बालेपन के इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की पिछले महीने आई रिपोर्ट पर कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग ने दोनों अधिकारियों को तलब किया है।

सीएम से मिले मंत्रालय के कर्मचारी ग्रेड-पे बढ़ाने की रखी बात

भोपाल। मंत्रालय के 50 से अधिक कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। ये मंत्रालय शीघ्रलेखन संघ के अध्यक्ष सुभाष वर्मा के नेतृत्व में उनसे मिले थे। सभी ने मुख्यमंत्री को नए साल की शुभकामनाएं दीं और प्रदेश के विकास में बेहतर काम करने का संकल्प दोहराया। सुभाष वर्मा व अन्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि मंत्रालय में काम करने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमानुसार ग्रेड-पे का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों के लिए बाहर के विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की तुलना में अलग ग्रेड-पे की अनुशंसा ब्रह्मस्वरूप समिति ने की थी। इसका पालन हो तो तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी लाभ होगा। इस पर मुख्यमंत्री ने विचार करने का भरोसा दिया है। यह मुलाकात हुई है।

मिस एमपी रूद्रप्रिया ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

भोपाल। फेमिना मिस एमपी 2020 रूद्रप्रिया यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। वे अखिल भारतीय स्पर्धा की तैयारी कर रही हैं। चौहान ने मध्य प्रदेश की बेटी को शुभकामनाएं दीं। रूद्रप्रिया के पिता डीके यादव ने बताया कि उनकी बेटी इस तरह की स्पर्धाओं में अर्जित पुरस्कार राशि से कैंसर पीड़ित बच्चों के इलाज में सहयोग करेंगी। रुद्रप्रिया वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल प्लानिंग नई दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में रिसर्च एसोसिएट के पद पर कार्यरत हैं।

ईओडब्ल्यू-लोकायुक्त में सीधी भर्ती के आईपीएस को ही बनाया जाएगा एसपी

पदोन्नति चाहिए तो लगेगी नौकरशाहों की पाठशाला

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

मप्र सरकार द्वारा नये साल के पहले ही दिन में प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन 67 अधिकारियों को पदोन्नति दी है, उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 33 अधिकारी ऐसे हैं, जिन्होंने पदोन्नति के लिए जरूरी प्रशिक्षण ही नहीं लिया है। इसके बाद भी सरकार द्वारा उन्हें कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और अधिसमय वेतनमान में सशर्त पदोन्नत कर दिया गया है। शर्त के मुताबिक उन्हें अगली मिड कैरियर ट्रेनिंग करना अनिवार्य होगा। उधर पुलिस विभाग भी वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नत करने के लिए केन्द्र को भेजे गए कैडर रिव्यू प्रस्ताव में अधीनस्थ पदों को समाप्त करने की अनुशंसा की गई है।

लगेगी प्रशिक्षण की पाठशाला

25 दिन के मिड कैरियर प्रशिक्षण जिन अधिकारियों ने नहीं किया है और उन्हें पदोन्नति दी गई है ऐसे अधिकारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के दो प्रमुख अधिकारियों में राजस्व आयुक्त जीवी रश्मि को पदोन्नत कर सचिव राजस्व बनाया गया है। साथ ही आयुक्त आदिवासी विकास संजीव सिंह को भी अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। लेकिन इन्हें इस शर्त पर पदोन्नति दी गई है कि ये चौथे चरण का आगामी मिड कैरियर प्रशिक्षण को पूरा करेंगे। इसी तरह 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 33 अधिकारियों को 9 वर्ष की सेवा पूरी किए जाने के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति दी गई है, उन्हें भी तीसरे चरण के मिड कैरियर प्रशिक्षण को पूरा करना होगा।

कामकाज सुधारने की चेतावनी

उधर, कैडर रिव्यू प्रस्ताव में भारतीय पुलिस सेवा के पदों में वृद्धि के लिए कई संस्थाओं में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की जगह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को पदस्थ करने की तैयारी की जा रही है। पदोन्नति व कई अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने की वजह से रिक्त चल रहे पदों पर पदस्थापनाएं होने की उम्मीद है। इसके साथ ही कई उन अधिकारियों को भी हटाया जाना तय माना जा रहा है, जो मौजूदा सरकार की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे हैं। इनमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से लेकर उच्च स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। दरअसल दो दिन बाद यानि कि चार जनवरी को कलेक्टर-कमिश्नर कान्फ्रेंस के बाद प्रदेश में कलेक्टर, आयुक्त सहित एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होना तय है। इस वीडियो कान्फ्रेंसिंग में पिछली बैठक में जिन जिलों का काम खराब रहा था, उन्हें काम सुधारने के लिए चेतावनी दी गई थी।

होगी अदला-बदली

अब चार जनवरी को सभी जिलों के कामकाज का पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री के पास फिर रहेगा। ऐसे में जिन जिलों में कामकाज रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, उन जिलों के कलेक्टरों को बदला जाना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही उन अधिकारियों में भी बदलाव किया जाना है जिनकी पटरी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नहीं बैठ रही है। माना जा रहा है कि इस फेरबदल में करीब एक दर्जन जिलों के कलेक्टरों के अलावा पदोन्नत होने वाले अधिकारियों की भी नई पदस्थापनाएं की जानी हैं।

मांगे यह पद

विशेष पुलिस महानिदेशक के दो पदों सहित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के आठ पद जिसमें साइबर क्राइम, आरएपीटीसी इंदौर, जेएनपीए सागर, पीटीआरआई भोपाल, एनटी नक्सल ऑपरेशन, नारकोटिक्स, एसटीएफ तथा ट्रेनिंग पुलिस मुख्यालय के अलावा 8 पद उप पुलिस महानिरीक्षक के बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही फील्ड में पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू के पद भी शामिल हैं।

इन संस्थाओं के लिए डीजी की तलाश

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल में महानिदेश के पद से आर.परशुराम के इस्तीफे के बाद नई नियुक्ति के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी की तलाश की जा रही है। इसी तरह से रेरा अध्यक्ष एंटोनी डिसा का सरकार द्वारा बीच कार्यकाल में ही समाप्त किया जा चुका है। इसकी वजह से यहां पर भी महानिदेशक का पद रिक्त चल रहा है। यही वजह है कि रेरा में भी डिसा की जगह नई पदस्थापना की जानी है। इसके लिए भी नए अधिकारी की तलाश की जा रही है।

भापुसे के लिए मांगे 39 नए पद

कैडर रिव्यू प्रस्ताव में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए 39 नए पदों की मांग की गई है। इसमें मुख्यालय में एक विशेष पुलिस महानिदेशक सहित चार पुलिस महानिरीक्षक के पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इन पदों के सरेंडर होने पर इतने ही पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया जा सकेगा। फिलहाल वर्तमान में कैडर पोस्ट 166 हैं, जिन्हें 205 किए जाने की मांग की गई है। इसके लिए तैयार किए गए कैडर रिव्यू प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका है। कैडर रिव्यू के प्रस्ताव के मुताबिक दोनों प्रमुख जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू तथा लोकायुक्त में अब किसी प्रमोटी अधिकारी को एसपी नहीं बनाया जाएगा। आयकर छापों के बाद एक प्रमोटी अधिकारी का नाम सामने आने के बाद इसमें संशोधन किया गया है। यह बात अलग है कि छापों में तीन वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के नाम भी शामिल हैं। इसी के चलते 39 नए पद मांगे जा रहे हैं, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद बढ़ाने सहित ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में सीधी भर्ती के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक बनाया जा सके। इसमें महानिदेशक का एक पद सहित पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड जबलपुर, पुलिस महानिरीक्षक पीटीआरआई, पुलिस महानिरीक्षक जेएनपीए सागर तथा पुलिस महानिरीक्षक आरएपीटीसी इंदौर का पद समाप्त करने की भी मांग की गई है।

भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का बयान

क्रीमी लेयर में हैं तो खुद छोड़ दें आरक्षण का लाभ : आर्य

धनंजय प्रताप सिंह ● भोपाल

कहा– पदोन्नति में आरक्षण कांग्रेस का पाप, नौकरी तक था, सेवा में शामिल कर लिया

देश हित में जिस तरह करोड़ों लोगों ने घरेलू गैस सिलिंडर की सब्सिडी छोड़ दी और सक्षम होने पर अन्य सरकारी सुविधाएं छोड़ रहे हैं, उसी तरह आरक्षण के चलते जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, उन्हें जरूरतमंदों के लिए खुद आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। यह कहना है भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य का। 'नवदुनिया' से विशेष बातचीत में आर्य ने आरक्षण, सियासत और बंगाल विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चर्चा की। उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि भाजपा सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। पेश है आर्य से बातचीत के प्रमुख अंश–

लाल सिंह आर्य

मप्र में 2018 के विस चुनाव में एससी वोट बैंक की वजह से भाजपा की हार हुई थी?

ऐसा नहीं है। उस चुनाव में भी हमने रीवा क्षेत्र की अधिकतर सीटों पर जीत हासिल की थी और सभी वर्गों का वोट भाजपा को मिला था। दरअसल कांग्रेस, बसपा और सपा जैसी पार्टियां कई वर्गों को बरगलाती रही हैं, जिससे कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है। तब 2 अप्रैल को हुई घटना इन्हीं दलों की साजिश का परिणाम थी, जिसके कारण असमंजस की मामूली स्थिति बनी थी। हम अनुसूचित जाति को भ्रमित करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि ये लोग गांधी और आंबेडकर का फोटो लेकर आंदोलन करते हैं लेकिन उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते।

● **सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे?**

जब तक समाज में बराबरी नहीं आ जाती आरक्षण समाप्त नहीं कर सकते। कानून हर विषय पर वह काम नहीं कर सकता, जो समाज में सामंजस्य से हो सकता है। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और वे क्रीमी लेयर में हैं, उन्हें आगे आकर आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए, जिससे जरूरतमंदों को फायदा मिल सके। जहां तक पदोन्नति में आरक्षण का सवाल है यह कांग्रेस का पाप है। संविधान में नौकरी मिलने तक आरक्षण की बात थी, जिसे कांग्रेस ने बिगाड़ते हुए सेवा में भी शामिल कर दिया। अब भाजपा पर ही दोष मढ़ते हैं, जबकि हम तो उनके किए पापों को किसी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा सभी वर्गों के हित के लिए काम कर रही है। भाजपा की सरकार ने ही पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े किए।

● **बंगाल के हालात को कैसे देखते हैं?**

ममता सरकार में टीएमसी कार्यकर्ताओं की शह पर बदमाशों ने वहां भाजपा के 131 कार्यकर्ताओं की हत्या की है। इनमें 105 कार्यकर्ता अनुसूचित जाति के हैं। कार्यकर्ताओं पर आंदोलन के बहाने केस लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, बल्कि हत्या की जा रही है। इसके खिलाफ हमने छह दिसंबर बाबा साहब आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर दिल्ली में धरना दिया था।

बच्चों को पढ़ाई में उत्कृष्ट बनाने अब पंचायतों में लगेगी मां की पाठशाला

ग्राम पंचायत भवन में बच्चे टीवी स्क्रीन पर करेंगे विषय का अध्ययन

भोपाल(आरएनएन)। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को विषय संबंधी पढ़ाई में उत्कृष्ट बनाने के लिए अब मां की पाठशाला लगाई जाएगी। जिस प्रकार घर में माता एवं दादा दादी बच्चों को दुलार के साथ पढ़ाती है। कुछ इसी प्रकार का माहौल बच्चों के लिए ग्राम पंचायत भवनों में सरकार द्वारा किया गया है। भोपाल के फंदा ग्रामीण बीआरसीसी क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं वहां पर कक्षा तीसरी से पांचवी तक के बच्चे मां की पाठशाला में पढ़ेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा जो नियम बनाया गया है, उसके तहत बच्चे स्कूल नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत भवन में पढ़ने जाएंगे। यहां पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में बड़ी टीवी की स्क्रीन लगाई गई है। इस स्क्रीन पर शिक्षकों द्वारा विषय संबंधित सीडी तैयार की गई है। इस सीडी का स्क्रीन पर प्रदर्शन होगा।

बच्चे अपनी माताओं के अलावा दादा और दादी के साथ भी स्क्रीन पर विषय का अध्ययन करने पहुंचेंगे। इस पढ़ाई में शिक्षक की पूरी मदद रहेगी, लेकिन प्रबंधन ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को संभालना होगा। इस संबंध में शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।

ग्रामीण बीआरसीसी कार्यालय में शिक्षकों की हुई बैठक

मां की पाठशाला को प्रभावी बनाने के लिए शाम फंदा ग्रामीण बीआरसीसी कार्यालय में जन शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समस्त जन शिक्षकों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बीआरसीसी रविंद्र जैन ने इस दौरान शिक्षकों को समझाईश दी की सरल और सुगम तरीके से बच्चे मां की पाठशाला में पढ़ाई कर सकें। हम सभी को मिलकर इस प्रकार के रास्ते निकालना होंगे। उन्होंने कहा है कि कोविड.19 का पालन करते हुए एलसीडी के माध्यम से बच्चों को विषय वस्तु का अध्ययन कराया जाए। इस दौरान समस्त शिक्षकों द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर शिक्षक रानी मेहरा, स्वाति देवताले, प्रमोद तिवारी, संजय झरबड़े, पर्वत सिंह, राजकुमारी, संजीता चौबे, विक्रम सिंह, भगवान सिंह, मोनिका जैन, संगीता चौरसिया सहित अन्य जन शिक्षक और शिक्षक मौजूद थे।

इनका कहना है...

मां की पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम सरकार की अभिनव पहल है। माता के साथ बच्चे उसी प्रकार अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार घर का माहौल रहता है।

संजीव कुमार गुप्ता, जन शिक्षक

हमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं। उसके अनुसार हम पूरा कार्य करेंगे। बच्चों को सामाजिक एवं व्यवहारिक परिवेश में शिक्षा प्रदान करने की यह एक अच्छी कोशिश है।

राकेश धनगर, जन शिक्षक

मां की पाठशाला कार्यक्रम निश्चित तौर पर बच्चों को उत्कृष्ट बनाएगी। क्योंकि माताओं के सामने बच्चे बैठकर कुछ अलग ही स्वभाव में पढ़ाई करते हैं। इसका बच्चों को लाभ होगा।

गुंजा साहू, शिक्षक

पहले दिन प्रदेशभर में हाई-हायर सेकंडरी स्कूलों के 1611 शिक्षकों ने दी परीक्षा

विरोध के बीच शिक्षकों की दक्षता परीक्षा शुरू स्क्रीनिंग और सेनिटाइजेशन के बाद मिली एंट्री

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कमजोर परिणाम देने वाले शिक्षकों की दक्षता परीक्षा रविवार से शुरू हो गई है। दो दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में पहले दिन प्रदेशभर में हाई-हायर सेकेंडरी स्कूलों के लगभग 1611 शिक्षकों की परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा के लिए राजधानी के शिवाजी नगर स्थित शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उमा विद्यालय को एग्जाम सेंटर बनाया गया था। जहां 15 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए। एग्जाम सेंटर पर शिक्षक सुबह 10 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए थे, जिन्हे 11: 50 तक एंट्री दी गई। इस दौरान मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग सहित सेनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा गया। इसके बाद 12 बजे से 3 बजे पेपर हुआ। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2019-20 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शून्य से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले एवं हाईस्कूल तथा हायर सेकंडरी स्कूल के कैचमेंट की माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों की दक्षता आकलन के लिए परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। पिछले साल भी दसवीं बोर्ड परीक्षा में 30 फीसदी से कम परिणाम लाने वाले स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा दो बार ली गई थी।

शास. सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को बनाया गया था सेंटर

सेंटर के अंदर जाने का इंतजार करते परीक्षार्थी।

आज होगी 6299 शिक्षकों की परीक्षा

इस परीक्षा में प्रदेश के 7 हजार 910 शिक्षक शामिल हो रहे हैं। जिसमें हाई-हायर सेकंडरी के 1611 एवं मिडिल स्कूलों के 6299 शिक्षकों की दक्षता का आकलन किया जाएगा। इन शिक्षकों में राजधानी के 35 शिक्षक शामिल हैं। जिसमें मिडिल स्कूल के 22 और हायर सेकंडरी के 15 शिक्षकों को शामिल किया गया है। सोमवार को मिडिल स्कूलों के 6299 शिक्षकों की परीक्षा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित की जाएगी।

कई शिक्षक संगठन नाराज: स्कूल शिक्षा विभाग के इस निर्णय के बाद कई शिक्षक संगठन परीक्षा को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इसके लेकर लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हालांकि विभाग के इस निर्णय पर संगठनों की नाराजगी का कोई असर नजर नहीं आया।

ठेस पहुंचाती है परीक्षा

इस प्रकार की परीक्षा शिक्षकों के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाती है। हमने स्कूलों में ईमानदारी से पढ़ाया है।

रितु शर्मा, शिक्षिका

परीक्षा नहीं होना चाहिए

हमने स्कूलों में नियमित पढ़ाकर बच्चों को पढ़ाया है। इस प्रकार से शिक्षकों की परीक्षाएं नहीं होना चाहिए।

अफरोज मोहम्मद, शिक्षक

राजधानी के 35 शिक्षक देंगे परीक्षा

सेंटर के मुख्य गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग करते कर्मचारी।

फेल हुए तो मिल सकती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति

शिक्षकों की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी दिन किया जा रहा है। वहीं रिजल्ट भी गोपनीय रखा जाएगा। परीक्षा परिणाम कम होने पर शिक्षकों को दो माह की अवधि दक्षता सुधार के लिए दी जाएगी। जिला स्तर के इन शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद मार्च के पहले सप्ताह में दोबारा परीक्षा होगी। इसमें भी शिक्षक फेल होते हैं तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी सकती है।

अनुपस्थित शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

संपूर्ण कार्रवाई पर नजर रखेंगे। परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को उसी दिन कारण बताओ सूचना पत्र देकर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

पुस्तक देखकर किया पेपर हल

परीक्षा ओपन बुक पैटर्न पर आयोजित की जा रही है। इसके तहत शिक्षक पाठ्य पुस्तक रखकर परीक्षा दे रहे हैं। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त वे गाइड आदि का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

एंकर स्टोरी परीक्षा के विरोध में दतिया में शिक्षकों ने गृहमंत्री का किया घेराव, रीवा में भी हंगामा, आज दस हजार से अधिक शिक्षकों की होगी परीक्षा

हाई स्कूल व हायर सेकंडरी के 1545 शिक्षकों ने किताब देखकर दी परीक्षा, राजधानी में छह शिक्षकों के नंबर कम

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी के 1545 शिक्षकों ने रविवार को किताब देखकर परीक्षा दी। पहले दिन की परीक्षा में 90 शिक्षक अनुपस्थित रहे। सोमवार को दस हजार से अधिक शिक्षक परीक्षा देंगे। राजधानी में पहले दिन की परीक्षा में 15 शिक्षक शामिल हुए। इसमें किताब देखकर परीक्षा देने वाले छह शिक्षक ऐसे निकले, जिनके 50 से कम नंबर आए हैं। पेपर सी नंबर का आयोजित किया गया था। सत्र 2019-20 में दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम 40 फीसदी से कम आया है। उन स्कूलों के शिक्षकों की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दक्षता मूल्यांकन रविवार से शुरू किया। इस परीक्षा में पहले दिन रविवार को हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी के 1655 शिक्षकों में 1545 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में 90 शिक्षक अनुपस्थित रहे। सोमवार को मिडिल स्कूल के दस हजार से अधिक शिक्षकों की परीक्षा होगी। 4 जनवरी को परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इसमें सभी विषयों के शिक्षकों की परीक्षा होगी। राजधानी में परीक्षा केंद्र एक्सीलेंस स्कूल रहेगा।

सोलह शिक्षकों को मिली थी अनिवार्य सेवानिवृत्ति : पिछले साल भी स्कूल शिक्षा विभाग ने दसवीं बोर्ड परीक्षा में 30 फीसदी से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा दो बार ली थी। दोबारा फेल होने पर प्रदेश के 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। गौरतलब है कि इस बार शिक्षक संगठन परीक्षा विरोध कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों को विभाग के आला अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है कि शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जाएगी। हालांकि पिछले परीक्षा के समय भी शिक्षक संगठनों को यही आश्वासन मिला था। बावजूद इसके शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई।

दतिया-रीवा में शिक्षकों ने किया विरोध

परीक्षा के विरोध में दतिया में शिक्षकों ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का घेराव किया। गृहमंत्री ने शिक्षकों को सेवा से बाहर नहीं करने का आश्वासन दिया। रीवा में भी शिक्षकों ने परीक्षा का विरोध किया।

परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को नोटिस जारी

पहले दिन की परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले 90 शिक्षकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया गया है। उपयुक्त कारण होने पर (कोरोना संक्रमण इत्यादि) अनुपस्थित शिक्षकों की पुनः परीक्षा ली जाएगी। इस हेतु अलग से परीक्षा तिथि की सूचना दी जाएगी। नोटिस का जबाव तीन दिन में मांगा गया है। उपयुक्त जबाव नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी परीक्षा में फेल होने पर मिलेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति : शिक्षकों की परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन रविवार को ही किया गया। परीक्षा परिणाम गोपनीय रखा जाएगा। परीक्षा परिणाम कम होने पर शिक्षकों को दो माह की अवधि दक्षता सुधार के लिए दी जाएगी। जिला स्तर के इन शिक्षकों का ऑनलाईन प्रशिक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद मार्च के पहले सप्ताह में दोबारा परीक्षा होगी। इसमें भी शिक्षक फेल होते हैं, तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।

शिक्षक के सेवानिवृत्त होने बाद भी जारी किया नोटिस : बड़वानी जिले में उच्च श्रेणी शिक्षक अशोक सोलंकी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बावजूद इसके इनका नाम परीक्षा देने वाले शिक्षकों की श्रेणी में रखा गया। इतना नहीं सोलंकी सेवानिवृत्त होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हुए, तो बड़वानी डीईओ ने परीक्षा में शामिल नहीं पर कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया।

शत प्रतिशत उपस्थिति में भुला दी गई है केंद्र की गाइडलाइन

सैनिटाइजेशन व सफाई व्यवस्था पर नहीं दिया जा रहा ध्यान

कोरोना डर से दूर सरकारी कार्यालयों में अव्यवस्था बन रही जानलेवा

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

राज्य सरकार द्वारा जनकल्याण के कार्यों में गति लाने के लिए सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति जरूर अनिवार्य कर दी हो लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। भारत सरकार की जिस गाइडलाइन के तहत कार्यालयों का संचालन होना है उसका पालन दूर दूर तक नहीं देखा जा रहा है।

इधर देखें तो नियम का पालन ना होने के कारण सरकारी कार्यालयों में कोरोना का कहर कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 दिन पहले पंचायत राज संचालनालय में एक अफसर कोरोना पॉजिटिव आया है। इसकी दहशत नजदीक ईपीएफ कार्यालय में भी देखी जा रही है। महिला बाल विकास में कोरोना का प्रकोप अनवरत रूप से चल रहा है। यहां अभी भी बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंत्रालय में कोरोना का प्रकोप अपनी वही पुरानी गति लिए हुए हैं। रोकथाम के लाख दावे किए जा रहे हैं लेकिन प्रत्येक सप्ताह एक न एक कर्मचारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। अब यहां पर मरीजों की संख्या बढ़कर सैकड़ा पार कर चुकी है।

गाइडलाइन का पालन भी जरूरी

कर्मचारी जरूर कह रहे हो कि शत प्रतिशत उपस्थिति जरूरी है। जब सभी कर्मचारी ड्यूटी पर आएंगे तो जनता के काम आसानी से निराकृत होंगे। समय सीमा में लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। फाइलों में बंद लंबित प्रकरणों का निराकरण भी समय सीमा में पूरा हो पाएगा। कर्मचारियों के अनुसार शत प्रतिशत उपस्थिति कराने का शासन का निर्णय स्वागत योग्य। इसके साथ ही कार्यालयों में कोरोना गाइडलाइन का पालन होना भी उतना ही आवश्यक है। मंत्रालय से लेकर सतपुड़ा और विंध्याचल में शत प्रतिशत उपस्थिति के बीच महामारी लगातार पैर पसार रही है। कर्मचारियों का कहना कि विभागाध्यक्ष द्वारा न कार्यालय को सैनिटाइज कराया गया है ना ही सफाई व्यवस्था बनाई गई है। पानी की टंकियों में कीड़ों का प्रवेश है, मजबूरन यही पानी पीना पड़ रहा है।

शिक्षा के कार्यालयों में निरंतर सतर्कता जारी

शिक्षा के कार्यालयों में कोरोना की दहशत को देखते हुए निरंतर सतर्कता का क्रम जारी है। पिछले महीने लोक शिक्षण संचालनालय में शत प्रतिशत उपस्थिति होते ही अपर संचालक डीएस कुशवाहा ने सभी शाखाओं को आदेश जारी किया है। आदेश में श्री कुशवाहा ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि सभी कर्मचारियों को मास्क लगाकर कार्यालय में आना होगा। बाहरी व्यक्ति से संपर्क पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अल्कोहल युक्त सैनेटाइजर से हाथ साफ करना होगा। कर्मचारियों को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी। इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी कार्यालय में अनुपस्थित रहता है तो फिर उसे संबंधित शाखा प्रमुख को इस अनुपस्थिति का कारण बताना होगा। राज्य शिक्षा केंद्र माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा परिषद में डायरेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि शत प्रतिशत उपस्थिति के पालन में कर्मचारी नियम से कार्यालय ने अपनी आमद दर्ज कराएं। इसके साथ ही कोरोना से बचने के लिए जो सावधानी है। उस प्रक्रिया का भी पूरी तरह पालन करें। जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर बीआरसीसी कार्यालयों में भी कोरोना बचाव के लिए बाहरी लोगों का पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है।

विशेष अवकाश सहित अन्य समस्याओं को लेकर फिर सीएम को लिखा पत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन द्वारा सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारियों की 100 प्रतिशत संबंधी आदेश दिए लेकिन विशेष अवकाश संबंधी व्यवस्था का निर्धारण नहीं किया गया है। इसको लेकर एक बार फिर सरकार को पत्र लिखा गया है। शत प्रतिशत उपस्थिति संबंधी आदेश में लोक सेवकों ने संशोधित करने की मांग उठा दी है। इस संबंध में फिर से सरकार समर्थित राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। संगठन के महामंत्री राजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रालय सतपुड़ा और विंध्याचल से लेकर सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 100 प्रतिशत उपस्थिति के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में विरोधाभास की स्थिति सामने आ रही है। शर्मा का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में आए दिन कर्मचारी और अधिकारी संक्रमित हो रही हैं। अब आदेश में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि यदि कोई सेवक कोरोना से संक्रमित होता है तो फिर उसके विशेष अवकाश की क्या व्यवस्था होगी और उसका उपचार किस प्रावधान के तहत कराया जाएगा। राजेंद्र शर्मा का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में ड्यूटी करते हुए कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित होकर मौत के आगोश में समा चुके हैं। सरकार द्वारा ना तो इनके बीमा की व्यवस्था की गई है ना ही इन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह सभी व्यवस्थाएं भी सरकार को प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए करनी होगी। श्री शर्मा का कहना है कि कोरोना का प्रकोप भी कम नहीं हुआ है। प्रदेश में हर दिन एक ना एक कर्मचारी कोरोना संक्रमण का शिकार होकर दिवंगत हो रहा है। इस कारण कर्मचारियों को अवकाश सहित पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था तत्काल बनाना चाहिए।

आईटीआई गोविंदपुरा में प्लेसमेंट ड्राइव 5-6 को

भोपाल। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोविंदपुरा भोपाल में 5 एवं 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक युवा अपने मूल प्रमाण पत्रए बायोडाटा आदि के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, बीई (मैकेनिकल), आईटीआई तथा आयु 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदकों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। बिना मास्क के परिसर पर प्रवेश नहीं मिलेगा।

आज का इतिहास

- **1643** : मशहूर भौतिक विज्ञानी आइजक न्यूटन का जन्म।
- **1809** : ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म।
- **1931** : प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री निरुपा रॉय का जन्म।
- **1952** : भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर का जन्म।
- **1955** : सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता प्रताप चंद्र सारंगी का जन्म।
- **1965** : हिंदी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता आदित्य पंचोली का जन्म।
- **1966** : भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच भारत पाकिस्तान सम्मलेन की शुरुआत।
- **1972** : नयी दिल्ली में इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस का उद्घाटन।

आज का इतिहास

1925	गोपाल दास नीरज- कवि का जन्म हुआ।
1931	निरुपा रॉय अभिनेत्री का जन्म हुआ।
1994	राहुल देव बर्मन (आर. डी. बर्मन) हिन्दी फिल्मों के मशहूर संगीतकार का निधन हुआ।
1905	अयोध्याप्रसाद खत्री- खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि का निधन हुआ।
1998	बांग्लादेश ने भारत को उल्फा महासचिव अनूप चेतिया को सौंपने से इन्कार किया।
1999	मंगल ग्रह पर भाप का विश्लेषण करने हेतु अमेरिकी यान मार्स पौसर लैंडर प्रोब का प्रस्थान।
2002	ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भारत पहुँचे।
2004	भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाक प्रधानमंत्री जमाली के बीच इस्लामाबाद में वार्ता आयोजित।